(c) whether upgradation of MIG-27 aircrafts presently lying is hangers, in being considered as part of our negotiations with Russia; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MULAYAM SINGH YADAV): (a) The capabilities of the Indian defence forces are being continously upgraded and modernised in the light of factors such as regional and global security environment, advances in weapons, communication and other related technologies and the regional military balance and potential capabilities.

(b) to (d) It will not be in the interest of national security to disclose details of negotiations for and the acquisition of specific defence systems and technologies.

Manufacture of Air Defence Ship

807. SHRI SANJAY DALIMIA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to manufacture Air Defence Ship (ADS) indigenously;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether building of an Air Defence Ship may take upto 10 years and that the present levels of ships and submarines would drop considerably in a decade from now;

(d) if so, the cost likely to be incurred on the manufacturing of the said ship;

(e) whether the capacity utilisation of Mazagaon Dock Limited has been very low particularly on the submarine side which has been lying practically idle since may, 1994 and may lead to dissipation of such technical expertise; and

(f) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MULAYAM SINGH YADAV): (a) to (d) There is a proposal for construction of an Air Defence Ship (ADS) indegenously at an estimated cost of Rs. 1700 crores including spares. The construction of the ship is likely to take about 10 years after the Goernment sanction is accorded.

(e) and (0 In order to utilise the facilities created for construction of submarine at M/s. MDL, which is under utilised, letters of intent have been issued to the shipyard for construction of two submarines. Apart from this, part facility is utilised for ship repair/ construction of surface ships.

अनुदान के रुप में परिवर्तित किए गए कैंटीन लाभ

808. **प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने अपने कैंटीन लाभ में से 5 करोड़ रुपये एक संस्था को अनुदान के रुप में दिये हैं;

(ख) इस संस्था का नाम क्या है और उसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या यह सोसायटी रजिस्टर्ड है यदि हां, तो किस नाम से;

(घ) इस सोसायटी ने इस अनुदान का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया है; और

(ङ) क्या सोसायटी को अनुदान देने में नियमों का उल्लंघन हुआ है?

रक्षा मंत्री (श्री मलायम सिंह यादव): (क) और (ख) जी, हां। जिन अधिकारियों की सेवाएं स्थानांतरणीय हैं उनके बच्चों के वास्ते दिल्ली में एक स्कूल खोलने के लिए नई दिल्ली, स्थित सिविल सेवा सोसाइटी को मार्च, 1996 में 5 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। सोसाइटी के उद्देश्यों में दिल्ली या दिल्ली से बाहर ऐसी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना शामिल है जो अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र तथा गैर-सरकारी अधिकारियों के बच्चों के वास्ते खुली होंगी। सोसाइटी के उद्देश्यों में यह भी शामिल है कि दिल्ली में सिविल सेवा अधिकारी संस्थान की स्थापना की जाए।

(ग) यह सोसाइटी दिल्ली स्थित रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज के पास "सिविल सेवा सोसाइटी" के नाम और स्टाइल से पंजीकृत है।

(घ) सोसाइटी द्वारा स्कूल पर 12 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। सोसाइटी ने यह बताया है कि स्कूल